

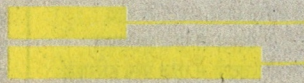
26 एकड़ में बना तालाब यमुना की बाढ़ से लबालब

दिल्ली में पानी की किल्लत होगी कम

79 लाख

लोगों को पानी सप्लाई की जा सकती है, जितना पानी यहां रिचार्ज हो रहा है उससे

प्रोजेक्ट की वजह से
बढ़ा परकोलेशन रेट



375 एमएम प्रति घंटे

800 एमएम प्रति घंटे हो गया है बढ़कर

भूजल में सस्पेंडेड सॉलिड (तेरने वाले ठोस पदार्थ) 100 यूनिट से भी कम है

Photo : Sunil Kataria

सरकार चला रही है यह प्रोजेक्ट, ग्राउंड वॉटर लेवल में हो रहा है इज़ाफा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

यमुना में इस बार आई बाढ़ से पल्ला बाढ़ क्षेत्र का रिजर्वयर लबालब भर गया है। लगातार पांचवें साल यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित है।

प्रोजेक्ट के लिए पल्ला बाढ़ क्षेत्र में सरकार ने लीज पर ली है जमीन

अधिकारी के अनुसार, इस बार वजौराबाद में यमुना नॉर्थ के पास पल्ला बाढ़ क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के लिए 26 एकड़ में गड्डे तैयार किए गए थे। यमुना

की पहली बाढ़ में इस बार जुलाई के पहले पखवाड़े में ही आ गई जिससे यह रिजर्वयर पूरी तरह भर गया है। रिजर्वयर में करीब 10 दिन से पानी भरा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह यमुना में आ रहे बाढ़ के पानी को रोकता है, जिससे राजधानी का भूजल स्तर बढ़े। इस तरह मॉनसून के दौरान यमुना में आए पानी से गर्मी के दिनों में राजधानी की प्यास बुझेगी।

इसके लिए 'परकोलेशन रेट' भी बढ़ाया गया है। परकोलेशन रेट जमीन के अंदर

पानी जाने की क्षमता है। जमीन की ऊपरी सतह सख्त होने की वजह से परकोलेशन रेट में कमी आ जाती है, इसलिए मॉनसून से पहले ऊपरी सतह को खोदा जाता है। पिछले चार वर्षों से इस प्रोजेक्ट के चार चरण पूरे किए जा चुके हैं। इसके लिए सुंगरपुर के पास दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर 26 एकड़ में तालाब तैयार की गई है। योजना के मुताबिक, तीन वर्ष के बाद इस प्रोजेक्ट को करीब एक हजार एकड़ में चलाया जाना था।

प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी ने बताया कि बीते चार वर्षों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। न सिर्फ परकोलेशन रेट बढ़ा है, बल्कि यमुना के आसपास के गांवों में भूजल स्तर

भी बढ़ गया है। अधिकारी के अनुसार, यमुना में जब बाढ़ आती है तो उसके पानी को रोकने के लिए बाढ़ क्षेत्र में कुछ फुट गहरे गड्डे किए जाते हैं। ये गड्डे पानी से भर जाते हैं और फिर धीरे-धीरे गड्डों का पानी जमीन के अंदर चला जाता है। पहले यह पानी बाढ़ के साथ बहते हुए दिल्ली के बाहर चला जाता था और इसका कोई लाभ दिल्ली को नहीं मिलता था। 26 एकड़ में तालाब बनाया गया है। भूजल स्तर को मापने के लिए इसमें 33 पीजेमीटर भी लगाए गए हैं। यह जमीन 94348 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिल्ली सरकार ने लीज पर ली है। हर साल इस प्रोजेक्ट पर करीब 52 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं।

बाढ़ के असर को भी कम कर सकता है

अगर इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर चलाया जाए तो यह बाढ़ के असर को भी कम कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए प्रोजेक्ट को चार वर्षों से 26 एकड़ जमीन पर ही चलाया जा सकता है। गड्डों में पानी भरने से यमुना का प्रवाह भी कम होगा और निचले इलाकों में पानी भरने के आसार कम होंगे।

पिछले वर्षों के दौरान कैसे रहे नतीजे...

विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 14 दिन, 2020 में 19 दिन, 2021 में 24 दिन और 2022 में अब तक 30 दिन यह क्षेत्र पानी में डूबा रहा है। 2021 में इसकी वजह से भूजल स्तर में 0.5 से 2.5 मीटर का इजाफा हुआ। वहीं, 2022 में इसकी वजह से भूजल स्तर में 0.7 से 2 मीटर तक का इजाफा हुआ है। अनुमान के मुताबिक, अकेले 2022 में इस रिजर्वयर की वजह से धरती के अंदर 2280000 क्यूबिक मीटर पानी रिचार्ज हुआ।

NBT
LENS

समझिए खबरों के अंदर की बात

क्यों जरूरी है रिजर्वयर?

यमुना में बाढ़ का एक पहलू ये भी है कि इसमें बनाया

गया रिजर्वयर भरने से भूजल स्तर बढ़ेगा। दरअसल, जिस तरह से दिल्ली में पेयजल की कमी है, उसे देखते हुए अंडरग्राउंड वॉटर की जरूरत है, ताकि गर्मियों में इस पानी का उपयोग किया जा सके। रिजर्वयर बनाने का

एक फायदा ये हुआ है कि पहले यमुना किनारे की जमीन सख्त हो गई थी इसलिए जमीन के नीचे पानी धीमे जा रहा था, लेकिन रिजर्वयर बनने से जमीन नरम हो गई और जमीन के नीचे तेजी से पानी जाने लगा। एक अनुमान है कि यमुना के मौजूदा रिजर्वयर से जितना पानी नीचे गया, उससे 75 लाख लोगों की एक दिन की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है।